भारत का संघ

बनाम

वी. श्री शंकर टेक्सटाइल्स एक्स-एम्प्लॉइज यूनियन एंड अन्य

सितंबर 14, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.)

श्रम कानूनः

कपड़ा मिल को बंद करना- कपड़ा श्रमिक पुनर्वासन निधि योजना-बंद मिल के श्रमिक संघ द्वारा योजना के लाभ का दावा करते हुए रिट याचिका पेश की-उच्च न्यायालय ने योजना में उन शर्तों को रखते हुए रिट याचिका के लिए अनुमति इस मत के साथ दी कि योजना के अन्तर्गत मिल को बंद करने के सम्बन्ध में जो शर्तें धारा 25-व औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित हैं वह असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और विवेकाधीन हैं-उच्च न्यायालय ने उद्योग विवाद अधिनियम की धारा 25-व से संबंधित शर्त को आधारहीन ठहराने के लिए किसी भी प्रशंसनीय कारण का संकेत नहीं दिया है-इसके अलावा, दस्तावेज स्पष्ट रूप से मिल के तथ्यात्मक रूप से बंद होने की तारीख को 09.10.1984 के रूप में दर्शाते हैं-उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत ठहराने में त्रुटि की-उच्च न्यायालय की एकल पीठ व खण्ड पीठ के आदेशों को अपास्त कर दिया-औद्योगिक

विवाद अधिनियम, 1947 - 25-व-भारत सरकार की कपड़ा नीति, 1985- कपड़ा श्रमिक पुनर्वासन निधि योजना, 1991।

भारत सरकार ने 6.6.1985 पर कपड़ा नीति की घोषणा की। उक्त वस्त्र नीति के तहत, वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना (टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस.) उन कपड़ा इकाइयों के स्थायी रूप से बंद/परिसमापन होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी, जिसका उत्पादन 5.6.1985 के बाद समाप्त हो जाता। प्रत्यर्थी नं. 1 संघ श्री शंकर टेक्सटाइल मिल्स, जो दिनांक 09.10.1984 से बंद कर दी गई थी, ने श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस. के तहत लगाई गई शर्तें कि मिल को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-व के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए था या शासकीय परिसमापक नियुक्त किया जाना चाहिए था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, और संघ के सदस्यों को मौद्रिक लाभों सहित टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस. के लाभों का विस्तार करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि शर्तें असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और परिणामस्वरूप विवेकाधीन थी। खण्ड पीठ ने रिट अपील में निष्कर्षों को बरकरार रखा और भारत संघ ने तत्काल प्रभाव से अपील

पेश की।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दृष्टिगत नहीं रखा है कि योजना के तहत योग्यता को आकर्षित करने के लिए सभी चार शर्तों को पूरा किया जाना था और चूंकि उक्त शर्तों में से दो शर्तें प्रत्यर्थी-संघ द्वारा संतुष्ट नहीं की गई थीं, इसलिए योजना को आकर्षित नहीं किया गया था और इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि कैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-व और / या शासकीय परिसमापकों की नियुक्ति के संदर्भ में बंद करने के संबंध में शर्तें संवैधानिक रूप से अपोषणीय थीं।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 उच्च न्यायालय ने कोई प्रशंसनीय कारण नहीं बताया है। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-व से संबंधित शर्त अवैध, विधि विरूद्ध और किसी तरह से तर्कहीन थी। बिना कारण बताए नीतिगत निर्णय को अवैध नहीं माना जाना चाहिए था। इसलिए उच्च न्यायालय की एकल और खण्ड पीठ के आदेश अपोषणीय हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि योजना में निर्धारित शर्तों के कुछ हिस्सों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

1.2. इसके अलावा, अभिलेख पर दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि मिल में काम का ठहराव दिनांक 09.10.1984 से था।

यह स्वयं कर्मचारियों को योजना के तहत लाभों से वंचित कर देता है। उच्च न्यायालय का यह विचार कि यद्यपि 1984 में भौतिक रूप से बंद किया गया था, औपचारिक रूप से बंद करने की तारीख उस तारीख को होगी जिस दिन संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे, नीति की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है जिसमें उस तारीख का उल्लेख किया गया है जिस दिन मिल बंद हुई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय की एकल और खण्ड पीठ के आदेशों को खारिज कर दिया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2000 की सिविल अपील सं. 5495

1999 की रिट अपील संख्या 2246 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के 24.07.1999 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

विकास सिंह, एएसजी, डी. एस. मेहरा, सुनीता शर्मा और बी. कृष्ण प्रसाद अरोड़ा (शिव कुमार सूरी के लिए), रमेश एस. जाधव, विक्रांत यादव, अमित के. अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थीयों के लिए चावला और संजय आर. हेगड़े।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को दी गई है जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी संख्या 1-संघ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करने के लिए एक रिट याचिका दायर की कि कपड़ा श्रमिक पुनर्वास निधि योजना (संक्षेप में श्टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस.श) के तहत इस प्रभाव से लगाई गई शर्तें कि मिल को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में श्अधिनियमश) की धारा 25-0 के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए था या आधिकारिक परिसमापकों को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और 16 (संक्षेप में श्टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस.श) का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया जाना चाहिए था। संविधान श) और संघ के सदस्यों को सभी के साथ टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस. के लाभों का विस्तार करने के लिए अनिवार्य रिट द्वारा अपीलार्थियों को निर्देश देने के लिए। मौद्रिक लाभ सहित परिणामी राहत।

3. रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्व-उल्लिखित शर्तें असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण थीं और इसलिए मनमाना थीं।

4. रिट अपील को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत

किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तथ्य यह है कि पात्रता को आकर्षित करने के लिए चार शर्तों को पूरा किया जाना था योजना के तहत। निर्विवाद रूप से संघ के सदस्यों द्वारा दो शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई कारण नहीं बताया गया है कि कैसे बंद करने के संबंध में शर्तें अधिनियम की धारा 25-ओ औरध्या आधिकारिक परिसमापकों की नियुक्ति संवैधानिक रूप से अस्थिर थी।

6. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने समर्थन किया आदेश दें।

7. अध्याय प् में वस्त्र नीति 1985 पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया थाः

1. कपड़ा उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अनूठा स्थान है। देश। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात आय में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह उद्योग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक प्रदान करता है। इसके द्वारा प्रदान किया गया रोजगार एक स्रोत है। लाखों लोगों के लिए आजीविका, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं। इसका निर्यात हमारे कुल का एक बड़ा हिस्सा है। विदेशी मुद्रा आय। स्वस्थ विकास और तीव्र विकास इसलिए इस उद्योग का बहुत महत्व है।

2. पिछले कुछ वर्षों में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है मार्च 1981 में घोषित नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित किया गया। जबकि तब से कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। इस नीतिगत ढांचे के तहत कपड़ा नीति के उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है वस्त्र नीति विवरण में पूरी तरह से हासिल नहीं किया गया है। इस प्रकार यह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या अभी भी बहुत निचले स्तर पर है। वहाँ है। बीमारी की घटनाओं में वृद्धि का प्रमाण, विशेष रूप से संगठित मिल क्षेत्र, बड़ी संख्या में बंद इकाइयों में परिलक्षित होता है। टिकाऊ सिंथेटिक और मिश्रित उत्पादों की भारी मांग है जो असंतुष्ट है सस्ती कीमतों पर कपड़ा जो स्वदेशी लोगों द्वारा उत्पादन पूरा नहीं किया जा रहा है । कपड़ा उत्पादों की पूर्ण निर्यात क्षमता बनी हुई है, एहसास हुआ।

3. कपड़ा उद्योग ने अपने भाग्य में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है अतीत भी। हालाँकि वर्तमान कठिनाइयों का विश्लेषण उद्योग से पता चलता है कि उद्योग का वर्तमान संकट न तो है चक्रीय और न ही अस्थायी, लेकिन गहरी संरचनात्मक कमजोरियों का सुझाव देता है, इसलिए सरकार ने वर्तमान कपड़ा नीति की समीक्षा की है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस नई नीति को तैयार किया है भारत में कपड़ा उद्योग का दीर्घकालिक पुनर्गठन दृष्टिकोण।

8. वर्तमान विवाद शर्तों की वैधता से संबंधित है। राहत के भुगतान

के लिए चार शर्तों का शुल्क मानदंड अपीलार्थियों के अनुसार, दिनांकित डब्ल्यू. आर. एफ. एस. 1.5.1991 इस प्रकार हैंः

(i) इकाई मध्यम पैमाने की होनी चाहिए।

(ii) पीसने का पूर्ण विराम होना चाहिए।

(iii) धारा 25-ओ के संदर्भ में इकाई का समापन होना चाहिए।

(iv) अधिनियम के तहत परिभाषित एक अवैध हड़ताल जिसके कारण बंद हो जाता है मिल या तो अधिनियम की धारा 25-ओ के तहत या के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय जिस पर आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया जाता है योजना को अप्रयोज्य बनाता है।

9. यह इंगित किया गया है कि स्थितियाँ संचयी हैं और तुरंत मामले की शर्तें (पप) और (पपप) पूरी नहीं होती हैं। बंद अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत सुलह के संदर्भ में था और उत्पादन 5.6.1985 से पहले बंद हो गया था। रिट आवेदन में इस आधार पर नीति को कोई चुनौती नहीं दी गई थी कि शर्तें (पप) और (पपप) तर्कहीनता और भेदभाव से ग्रस्त थीं।

10. यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

11. बिना कारण बताए नीतिगत निर्णय को अवैध नहीं माना जाना चाहिए था।

12. यह बताया गया है कि 30.5.1986 पर एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचा गया था और रिकॉर्ड पर रखे गए सभी दस्तावेजों से यह स्पष्ट था कि मिल 9.10.1984 पर बंद थी।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-संघ ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 25-ओ के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को आहत किया। एक योजना के लाभकारी होने का उद्देश्य श्रमिकों को लाभान्वित करना है और यही योजना का उद्देश्य था। यह बताया गया है कि संघ के सदस्य सभी श्रमिक एक बंद कपड़ा मिल में उसके बंद होने की तारीख को कार्यरत होते हैं। वे लगभग पाँच साल से लगातार काम कर रहे थे और मजदूरी कमा रहे थे। त्े.1600 ध्- च. उ. जब बंद हुआ तब वे किसी अवैध हड़ताल पर नहीं थे। उनके अनुसार, हालांकि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे 30.5.1986 , इसे बहुत बाद में प्रभावी किया गया था और इसलिए, प्रासंगिक तिथि 30.10.1986 होनी चाहिए। चूँकि प्रबंधन अंतिम लाभ डब्ल्यू. ई. एफ. 30.5.1986 का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था और इसका भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाना था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादन 5.6.1985 से पहले बंद पाया गया था।

14. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने कोई प्रशंसनीय कारण नहीं बताया है यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अधिनियम की धारा 25-0

से संबंधित शर्त अवैध, विपरीत और किसी भी तरह से तर्कहीन थी। वास्तव में, नीतिगत निर्णय का तब तक लाभकारी प्रभाव होने की संभावना नहीं है जब तक कि यह तर्कसंगतता की कसौटी पर टिकाऊ न हो।

15. जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1-संघ द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि शर्तें क्यों आक्षेपित व्यक्ति तर्कहीन थे या संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा, अभिलेख पर दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि ठहराव सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है मिल में काम का डब्ल्यू. ई. एफ. 9.10.1984 था। वास्तव में मिल के दिनांकित 21.6.1989 पत्र ने क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर को संबोधित करते हुए संलग्न प्रोफार्मा में कहा कि ठहराव की तारीख और समय 10.10.1984 था और ठहराव पूरा हो गया था। इस इकाई को बंद करने का तथ्य आवेदन में बताया गया था और राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया था। यह आगे कहा गया कि पिछले छह महीनों से स्पिंडल उपयोग का सवाल ही नहीं उठा क्योंकि मिल 10.10.1984 के बाद से बंद थी। यह स्वयं कर्मचारियों को योजना के तहत लाभों से वंचित कर देता है। यद्यपि समझौता ज्ञापन पर 30.5.1986 पर हस्ताक्षर किए गए थे और अधिनियम की धारा 12 (3) के संदर्भ में सुलह के तहत बंद करना डब्ल्यू. ई. एफ. 30.5.1986 था, दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से इंगित

किया गया था कि बंद करने की तथ्यात्मक तिथि 9.10.1984 है अर्थात वह तारीख जिस पर मिल बंद हो गई थी। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत ठहराने में गलती की। केवल उसी आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

16. इसके अतिरिक्त, किसी भी कारण के अभाव में इंगित किया गया है विद्वत एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के बारे में कि अधिनियम की धारा 25-ओ से संबंधित निर्धारित शर्तें मनमाना कैसे हैं, आदेश अस्थिर हैं। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि योजना में निर्धारित शर्तों के कुछ हिस्सों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय का विचार था कि हालांकि 1984 में भौतिक रूप से बंद किया गया था, औपचारिक रूप से बंद करने की तारीख उस तारीख को होगी जिस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दृष्टिकोण उस नीति की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है जिसमें उस तारीख का उल्लेख किया गया है जिस दिन मिल बंद हुई थी।

17. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपील की जानी चाहिए - अनुमति दी जिसे हम निर्देशित करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साक्षी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।